

संक्षिप्त

समाचार

ब्लाक स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता संपन्न, बच्चों

को बांटे पुरस्कार

चित्रकूट। युवा कल्याण विभाग द्वारा मानिकपुर मे ब्लॉक स्तरीय ग्रामीण खेल लीग प्रतियोगिता कृष्क इंटर कॉलेज भौरी में संपन्न हुई।



प्रधानाचार्य रुद्र नारायण पांडेय बच्चों को पूरे जोश और लगन वा खेल भावना से प्रतिभाग के लिये प्रोत्साहित किया व खेल से मानसिक वा शारीरिक विकास होता हे बताया गया था खेलो में सरकार की मंशानुरूप अपना कैरियर वा समाज को अनुशाशित वा प्रगति हेतु आगे बढ़ने को प्रोत्साहित किया गया। क्षेत्रीय युवा कल्याण अधिकारी अखण्ड प्रताप यादव द्वारा 100 मीटर सब जूनियर वर्ग की बच्चियों को हरी झंडी दिखाकर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। प्रतियोगिता में लंबी कूद में गरिमा साकेत जूनियर, रंजना सब जूनियर में, रंजीता सीनियर में प्रथम आई। डिस्कस में कमलेश सीनियर में, सुरेन्द्र जूनियर में, अकित सब जूनियर में प्रथम आये। गोला में कमलेश सीनियर में, सुरेन्द्र जूनियर में, अकित कुमार सब जूनियर में प्रथम आए। 1400 मीटर दौड़ में अनुराग पाल जूनियर में, जया बालिकाओं में जूनियर, गिरिजेश सीनियर में प्रथम आए। 100 मीटर में गरिमा जूनियर में, रामधारी सीनियर में,गुडिया सीनियर बालिका में, करुणा सब जूनियर बालिका में, ललित कुमार सब जूनियर, अनुराग पाल जूनियर में प्रथम आए। 200 मीटर में जितेंद्र जूनियर में, जया जूनियर बालिका, गिरिजेश , गुडिया। लंबी कूद में अनुराग पाल अजय, ललित प्रथम आए। बैडमिंटन, कुश्ती, वॉलीबॉल फुटबॉल में मधेयन, भौरी, ऐंचवारा का ख़दबा रहा। कार्यक्रम का समापन बच्चों को लंच और पुरस्कार में मेडल और प्रमाण पत्र देते हुए समापन किया गया। निर्णायकों में अवधेश सिंह जिला खेल सचिव, अमृत लाल क्रीड़ा प्रभारी, श्रीकेश, विनोद सिंह, चंद्रभान व क्षेत्रीय युवा कल्याण अधिकारी पहाड़ी उदयभान व युवक मंगल दल अध्यक्ष भौरी कमलेश कुमार मौजूद रहे।

जिला जज ने प्रशासनिक अधिकारियों की बैठक ली

चित्रकूट। आगामी 14 दिसंबर को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत को सफ़ल बनाने के लिये विकास कुमार प्रथम जनपद न्यायाधीश की अध्यक्षता में प्रशासनिक विभागों के अधिकारियों की तृतीय चरण की बैठक सम्पन्न हुयी। बैठक मे नीलू मैनवाल सचिव अपर जिला जज ने बताया कि अध्यक्ष जनपद न्यायाधीश द्र आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिक से अधिक पादों को चिन्हित कर निस्तारण के लिये बल दिया। सभी अधिकारियों से अपेक्षा की अपने अपने विभागों से सम्बन्धित मामले, जिनकों लोक अदालत के माध्यम से निस्तारित किया जा सके, को अधिक से अधिक चिन्हित कर उनमें पक्षकारों को कम से कम दो चार नोटिस तामीला करते राष्ट्रीय लोक अदालत में निस्तारित करने का प्रयास करें। बैठक में राममणि पाठक अपर जिला जजनोडल अधिकारी लोक अदालत, आरपी शुक्ल जिला कृषि अधिकारी, मुलायम सिंह सहायक अभियन्ता जल संस्थान, शारद कुमार पाण्डेय वरिष्ठ निरीक्षक विधिक माप विज्ञान, पंकज कुमार मिश्र जिला प्रोबेशन अधिकारी, कमलाकान्त शुक्ला एसएफ आई एनपीपी, बीएल गुप्ता बाल विकास परियोजना अधिकारी, बलराम सहायक अभियन्ता लोक निर्माण विभाग उपस्थित रहे।

एडीएम न्यायिक ने की समीक्षा बैठक, ठेकेदारों पर जतायी नाराजगी

चित्रकूट। अपर जिलाधिकारी न्यायिक राजेश प्रसाद की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में निर्धारित कार्ययोजना के अनुसार परिवहन ठेकेदारों द्वारा ट्रक उपलब्ध न कराये जाने पर नाराजगी व्यक्त की गई और हार्डिट ट्रॉसपोर्ट के विरुद्ध कारणा बताओ नोटिस निर्गत करने के निर्देश दिए गए।इस्टेट वेयरहाउस और एफ़सीआई को पर्याप्त संख्या में लेबर उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। समय से रिलीज आर्डर निरस्त कराकर समयबद्ध रूप से खाद्यान्न का उठान कर लाभार्थियों तक पहुंचाया जाए। अब किसी भी माह खाद्यान्न उठान समय विस्तार कराने के स्थिति उत्पन्न न हो। ट्रकों का आनलाइन ट्रैकिंग करते रहें और मानक का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध कार्यवाही प्रस्तावित करें।

28 को आर्येगे साइबर विशेषज्ञ, लगार्येगे जागरूकता शिविर

चित्रकूट। जिला मजिस्ट्रेट शिवशरणप्पा जीएन ने बताया कि मोहित बजाज (अधिवक्ता) साइबर एक्सपर्ट एण्ड टीम 28 नवम्बर को फ़ैर्रिसिक साइंस, साइबर अपराध, साइबर कानून एवं अन्य संबंधित विषयों पर जनपद में जागरूकता शिविर के कार्यक्रमों को आयोजित किया जाना प्रस्तावित है। उन्होंने बताया कि जनपदीय पुलिस द्वारा पुलिस अधीक्षक कार्यालय में उक्त शिविर कार्यक्रम का आयोजन किया जायेगा।

मुस्कान हत्याकांड का खुलासा न होने पर व्यापारियों ने फिर किया प्रदर्शन, डीएम को सौंपा ज्ञापन

चित्रकूट। राष्ट्रीय जन उद्योग व्यापार संगठन ने मुस्कान हत्याकांड का खुलासा न होने पर व्यापार संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित गुप्ता ने चित्रकूट आकर पीड़ित व्यापारी शिव नरेश अग्रहरी से मुलाकात की व पूरी घटना की जानकारी ली तथा जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। राष्ट्रीय जन उद्योग व्यापार संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित गुप्ता के नेतृत्व में राष्ट्रीय महामंत्री संगठन शानू गुप्ता के साथ सैकड़ो व्यापारियों ने पीड़ित व्यापारी के घर जाकर मुलाकात की तथा जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा मुस्कान हत्याकांड घटना के जल्द ही खुलासे की मांग की तथा पुलिस अधीक्षक से फोन द्वारा वार्ता की गई कोई निर्दोष न फंसे इस मामले में दोषी के ऊपर ही कार्यवाही हो। जिलाधिकारी ने जल्द ही कार्रवाई का भरपोसा देते हुए व्यापारी को सुरक्षा का भरपोसा दिया की बेटी मुस्कान के हत्यासा के गिरफ्तार कर कड़ी से कड़ी सजा दिए जाने की मांग की गई। इस मौके पर विनोद प्रिंस केसरवानी, प्रमोद जायसवाल, शकुंतला गुप्ता राम गुप्ता, सुधीर अग्रहरि, राजेश साहू, विष्णु केसरवानी, रूपेश निगम, नारायण दास गुप्ता, अरविंद कुमार कसौधन, रविवराज अग्रहरी, नरेंद्र कुमार, सुशील कुमार पांडे, आनंद बाबा, राजू चौरसिया मौजूद रहे ।

वैधानिक सूचना

पाठकों को सलाह दी जाती है किसी विज्ञापन पर किसी भी प्रतिक्रिया से पहले विज्ञापन में प्रकाशित किसी उत्पाद या सेवा के बारे में अपनी पूरी तरह जांच पड़ताल कर लें। यह समाचार पत्र उत्पाद या सेवा की गुणवत्ता या विज्ञापनदाता आदि के निवर्णन के बारे में विज्ञापन दाता द्वारा किए गए बवे या उल्लेख की पुष्टि या समर्थन नहीं करता। समाचार पत्र में प्रकाशित किसी भी प्रकार के विज्ञापन में पाठकों को सावधान किया जाता है कि कोई भी प्रतिक्रिया करने से पहले विज्ञापन के बारे में पूर्ण जांच पड़ताल कर लें तब आगे बढ़ें। समाचार पत्र उपरोक्त किसी भी विज्ञापन के बारे में किसी पाठक के प्रति उत्तरदायी नहीं होगा।

बिहार/झारखंड

संयुक्त किसान मोर्चा,केन्द्रीय श्रमिक संगठन ,खेत मजदूर संगठन का संयुक्त मंच

(**वर्ल्ड न्यूज फीचर नेटवर्क**)

बेतिया। संयुक्त किसान मोर्चा, केन्द्रीय श्रमिक संगठन,खेत मजदूर संगठन के संयुक्त मंच के आह्वाण पर देशव्यापी चेतावनी प्रदर्शन के मौके अखिल भारतीय किसान महासभा, अखिल भारतीय खेत ग्रामीण सभा,ऑल इंडिया सेंट्रल काँउंसिल ऑफ ट्रेड यूनियन (एक्टू), आदिवासी संघर्ष मोर्चा, बिहार राज्य गन्ना उत्पादक किसान महासभा, बिहार राज्य निर्माण मजदूर यूनियन, ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन (अइसा), इंकलाबी नौजवान सभा (इनोस) के संयुक्त तत्वावधान में बेतिया समाररणालय पर विशाल प्रदर्शन कर सभा किया गया।सभा को संबोधित करते हुए अखिल भारतीय किसान महासभा के राष्ट्रीय पाषंद व जिला अध्यक्ष सुनील

कुमार राव ने कहा,कि देश के विकास में मजदूरों, किसानों एवं अन्य मेहनतकश वर्गों का अहम योगदान है। उनकी उन्नति ही सही अर्थों में देश की प्रगति का सूचक है। लेकिन हमारे देश की सरकारें - चाहे केन्द्र की हो या राज्यों की - बड़े पूंजीपतियों, कारपोरेट घरानों और बड़े भूस्वामियों के निहित स्वार्थों में काम करती हैं। हमारे देश का शासक वर्ग साम्राज्यवादी शक्तियों के साथ साठगांठ करता है और साम्राज्यवादपरस्त नव उदारवादी नीतियों को लागू करता है। फलस्वरूप एक ओर जहां देश की आम जनता खासकर मेहनतकश अवाम बदहाली की शिकार है , वहीं मुझी भर अमीरों, धनगोस्टों, पूंजीपतियों, भूस्वामियों एवं लुट्टरों के पास देश की धन



सम्पदा का बड़ा हिस्सा गिरवी है। ऐसी हालात में हम जिला पदाधिकारी के माध्यम से सरकार से मांग करना चाहते हैं कि सी 2+50 फीसदी के आधार पर एमएसपी की कानूनी गारंटी के साथ सभी फसलों की खरीद की गारंटी की जाए।एक्टू

के जिला संयोजक जवाहर प्रसाद ने कहा कि बिजली क्षेत्र का निजीकरण न हो-कोई प्रिपेड स्मार्ट मीटर न लगाये जाएँ। कॉरपोरेट कम्पनियों के लिए अंधाधुंध भूमि अधिग्रहण बंद हो। भूमि अधिग्रहण कानून 2013 के प्रावधानों का

केवीके मधोपुर ने जनजातीय गौरव दिवस का किया आयोजन।

(**वर्ल्ड न्यूज फीचर नेटवर्क**)

बेतिया। डॉ. राजेंद्र प्रसाद केद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, पूसा, बिहार से संबद्ध कृषि विज्ञान केंद्र, मधोपुर ने 25 नवम्बर को भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में जनजातीय गौरव दिवस का आयोजन माडुआहा गांव मे किया। इस अवसर पर केंद्र ने जनजातीय किसानों के सशक्तिकरण और उन्नत कृषि तकनीकों के प्रचार-प्रसार के लिए एक विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम का भी आयोजन किया। यह कार्यक्रम केवीके मधोपुर के वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं प्रमुख डॉ. अभिषेक प्रताप सिंह के मार्गदर्शन मे हुई। प्रशिक्षण सत्र का संचालन विषय वस्तु विशेषज्ञ डॉ सौरभ दुबे ने किया। उन्होंने किसानों को फसल सुरक्षा के उन्नत उपायों की जानकारी दी और बताया कि जलवायु परिवर्तन एवं सीमित संसाधनों के बावजूद कृषि को अधिक लाभकारी बनाने के लिए कौन-कौन सी तकनीकों का उपयोग किया जा सकता है। इस अवसर पर केंद्र द्वारा 40 जनजातीय

किसानों को फूलगोभी की उन्नत किस्मों के पौध सामग्री का वितरण किया गया। डॉ. सौरभ दुबे ने कहा कि इस प्रकार के कार्यक्रम न केवल किसानों को प्रोत्साहित करते हैं, बल्कि उन्हें आत्मनिर्भर बनने में भी मदद करते हैं। उन्होंने भगवान बिरसा मुंडा के बलिदान और उनके द्वारा आदिवासी समाज के लिए किए गए कार्यों को भी याद किया। कार्यक्रम में किसानों ने बड़ी संख्या में भाग लिया और प्रशिक्षण के दौरान प्राप्त ज्ञान को अपने खेतों में लागू करने का आश्वासन दिया। यह आयोजन केवीके मधोपुर के प्रयासों और समाज के प्रति समर्पण का एक और प्रमाण है, जो आदिवासी किसानों को बेहतर कृषि तकनीकों और संसाधनों से परिचित कराकर उनकी आजीविका को सुदृढ़ करने का निरंतर प्रयास कर रहा है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य जनजातीय किसानों को सशक्त बनाना, उनके कृषि ज्ञान को उन्नत तकनीकों से समृद्ध करना और भगवान बिरसा मुंडा के प्रेरणादायक जीवन और

योगदान को जन-जन तक पहुंचाना था। केंद्र के पौधा रोग विशेषज्ञ श्री सौरभ दुबे ने कहा कि भगवान बिरसा मुंडा ने अपने छोटे से जीवनकाल में जनजातीय समाज के अधिकारों के लिए जो संघर्ष किया, वह हर किसान और ग्रामीण समुदाय के लिए प्रेरणा का स्रोत है। उन्होंने यह भी कहा कि केवीके का उद्देश्य जनजातीय किसानों को उन्नत कृषि तकनीकों और संसाधनों से परिचित कराना है, जिससे उनकी आजीविका में सुधार हो सके।

पौध सामग्री का वितरण

प्रशिक्षण के बाद केवीके मधोपुर की ओर से 40 जनजातीय किसानों को फूलगोभी की उन्नत किस्मों के पौध सामग्री का वितरण किया गया। यह पहल जनजातीय किसानों को आत्मनिर्भर बनाने और उनकी आजीविका को बेहतर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। ऐसे प्रयास किसानों को अपनी फसलों में वैज्ञानिक तरीकों का उपयोग करने के लिए प्रेरित करते हैं, जिससे उनकी पैदावार और आय

संविधान एवं लोकतंत्र की मजबूती को आगे आए नई पीढ़ी।

सत्याग्रह रिसर्च फाउंडेशन,मदर ताहिरा चैरिटेबल ट्रस्ट ने संविधान दिवस पर नई पीढ़ी

के युवाओं, न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका एवं मीडिया के लोगों से अपील की।

>>> संविधान दिवस के अवसर पर सत्याग्रह रिसर्च फाउंडेशन, मदर ताहिरा चैरिटेबल ट्रस्ट एवं विभिन्न सामाजिक संगठनों द्वारा एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया।



कुमार लोहिया, वरिष्ठ पत्रकार सह संस्थापक मदर ताहिरा चैरिटेबल ट्रस्ट डॉ. अमानुल हक, समाजसेवी नवीनदु चतुर्वेदी, पश्चिम चंपारण कला मंच की संयोजक शाहीन प्रवीण ने संयुक्त रूप से कहा कि आज 26 नवंबर को पूरे देश में संविधान दिवस मनाया जा रहा है। 26 नवंबर को विश्व में अपनाया गया सबसे लंबा संविधान है। वर्तमान में हमारे संविधान में 470 अनुच्छेद, 25 धाराएं और 12 अनुसूचियां हैं और साथ ही 5 परिशिष्ट भी हैं। इस अवसर पर वक्ताओं ने कहा कि संविधान दिवस मनाना जाता है। इस अवसर पर वक्ताओं ने कहा कि 395 अनुच्छेदों वाले भारतीय

संविधान में अब 470 अनुच्छेद रह गए हैं। संविधान सभा को भारतीय संविधान बनाने में 167 दिन लगे थे, जिसके लिए 11 सत्र आयोजित किए गए थे। अपने मूल स्वरूप में भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद, 22 धाराएं और 8 अनुसूचियां हैं। हमारे संविधान में कुल 1,45,000 शब्द हैं, जो पूरे विश्व में अपनाया गया सबसे लंबा संविधान है। वर्तमान में हमारे संविधान में 470 अनुच्छेद, 25 धाराएं और 12 अनुसूचियां हैं और साथ ही 5 परिशिष्ट भी हैं। इस अवसर पर वक्ताओं ने कहा कि संविधान दिवस मनाना जाता है। इस अवसर पर वक्ताओं ने कहा कि 395 अनुच्छेदों वाले भारतीय

में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों और कई अन्य संस्थानों में संविधान दिवस के अवसर पर विभिन्न भाषण, संवाद, वाद-विवाद प्रतियोगिताएं, प्रश्नोत्तरी आदि का आयोजन किया जा रहा है इस अवसर पर वक्ताओं ने नई पीढ़ी के युवाओं, पत्रकारों, मीडिया कर्मियों, न्यायपालिका, विधायिका, कार्यपालिका एवं आम जनता से संविधान एवं लोकतंत्र की मजबूती के लिए आगे आने की अपील की। उन्होंने कहा कि भारतीय संविधान का उद्देश्य लोकतंत्र की मजबूती है। नागरिकों के बीच संविधान के मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा प्रतिवर्ष 26 नवंबर को ह्रासविधान दिवस के रूप में मनाने का निर्णय 19 नवंबर 2015 को सामाजिक न्याय एवं अधिकांशित मंत्रालय द्वारा अधिसूचित किया गया था। इस अवसर पर वक्ताओं ने कहा कि भारतीय संविधान लोकतंत्र की मजबूती का आधार है। भारत को एक लोकतांत्रिक कल्याणकारी देश बनाने में भारतीय संविधान की महत्वपूर्ण भूमिका है।

अपर एसपी ने मिशन शक्ति अभियान के तहत महिलाओं व बालिकाओं को किया जागरूक

यातायात माह के तहत कालेज में अध्ययनरत 51 छात्राओं को वितरित किए गए निःशुल्क हेलमेट

■ महोबा



अपर पुलिस अधीक्षक वन्दना सिंह की अध्यक्षता में मुख्यालय महोबा थाना कोतवाली नगर महोबा क्षेत्रअन्तर्गत अवस्थित माँ0 चन्द्रिका महिला महाविद्यालय में यातायात जागरूकता माह नवंबर तथा मिशन शक्ति फेज 5.0 अभियान के तहत जागरूकता काशशला का आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम के मुख्य बिन्दु साइबर सुरक्षा, मिशन शक्ति और यातायात नियमों के प्रति जागरूकता पर आधारित कार्यशालाएँ थीं।

पहले सत्र में ‘साइबर सुरक्षा’ पर आयोजित किया गया। इस अवसर पर साइबर अपराध के बारे में छात्राओं को सतर्क रहने के लिए कहा। उन्होंने पोर्टल और साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 के बारे में विस्तृत जानकारी दी जिसके माध्यम से शिकायत दर्ज कराने और धोखाधड़ी से बचाव के बारे में बताया।

दूसरे सत्र में मिशन शक्ति अभियान के फेज-5.0 के तहत महिला सशक्तिकरण पर छात्राओं को मिशन शक्ति के विशेष अभियान (फेज-05) के तहत कम्युनिटी पुलिसिंग एवं महिला सशक्तिकरण हेतु विभिन्न योजनाओं के बारे में जानकारी देकर जागरूक किया गया।

तीसरा सत्र यातायात माह नवम्बर के तहत यातायात जागरूकता पर आधारित था, जिसमें सभी छात्राओं को यातायात नियमों जैसे स्टॉप-गो-स्टो,

हेलमेट, सीट बेल्ट, गति सीमा का पालन, यातायात निर्देशों, वाहन चलाते समय कभी भी मोबाइल को उपयोग न करना आदि के बारे में जागरूक किया गया।

इसी क्रम में छात्राओं ने रंगोली, चित्रकला एवं निबन्ध प्रतियोगिता के माध्यम से यातायात सुरक्षा के सम्बन्ध में अपनी प्रतिभा को परिलक्षित किया है, अपर पुलिस अधीक्षक द्वारा सभी छात्राओं की प्रशंसा कर उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की गयी है, विजेताओं को यातायात

सड़क सुरक्षा माह के समापन 30 नवंबर पर पुरस्कृत किया जाएगा। यातायात माह नवंबर के तहत आयोजित कार्यशाला में महाविद्यालय में स्कूटी से आने वाली अध्ययनरत 51 छात्राओं को निःशुल्क हेलमेट वितरित किये गये व सभी से अपील की गयी है कि वाहन चलाते समय हेलमेट अवश्य पहने, जिन्दगी अनमोल है, इसको बचाने के लिए सावधानी व सुरक्षात्मक उपायों के साथ यातायात नियमों का सदैव पालन करें। इस दौरान प्रभारी यातायात महोबा श्री सुनील कुमार सिंह, प्रभारी महिला थाना श्रीमती सुष्मा चौधरी, महाविद्यालय प्रिंसिपल गुप्ता, महाविद्यालय के सम्मानित शिक्षकगण, अध्ययनरत छात्राओं सहित महिला थाना एवं यातायात पुलिस टीम के अन्य अधिकारी/कर्मचारीगण मौजूद रहे।

लोकतंत्र की शान

सखी से पालन हो। खेराग्रश के सचिव संजय राम ने कहा साठ वर्ष से अधिक उम्र के सभी बुजुर्ग व युद्ध खेत मजदूरों एवं किसानों के लिए 10000 रुपए की मासिक पेंशन योजना लागू की जाए। किसान नेता हरे राम यादव ने कहा नई पेंशन स्कीम को खत्म कर पुराने पेंशन स्कीम को लागू किया जाए। भारतीय श्रम सम्मेलन प्रति वर्ष पुनः आयोजित किया जाए।किसान महासभा के नेता संजय यादव ने कहा कि मनरेगा में 200 दिन काम और 600 रुपये मजदूरी देने और इसे कृषि, पशुपालन और वाटर शेड आधारित योजना से जोड़ने की गारंटी की जाए। बिहार में डी. बंधोषिधाय्या भूमि सुधार आयोग की रिपोर्ट को सार्वजनिक किया जाए और उसकी सिफारिशों को लागू

किया जाए। किसान नेता इन्द्रदेव कुशवाहा ने कहा बिहार में एपीएमसी कानून के तहत कृषि मंडी को पुनर्बहाल किया जाए। बिहार में उचित जलप्रबंधन के जरिए बाढ़, जलजमाव एवं सुखाड़ की समस्या का स्थायी समाधान किया जाए। उत्तर कोयल एवं सोन नहर प्रणाली सहित तमाम सिंचाई परियोजनाओं का जीर्णोद्धार किया जाए। आदिवासी संघर्ष मोर्चा के जिला अध्यक्ष नंद किशोर महतो ने कहा कि वनाधिकार कानून 2006 को सख्ती से लागू किया जाए और वन क्षेत्र पर आदिवासियों के नैसर्गिक परम्परागत अधिकारों के सुनिश्चित किया जाए। अब्दुल खेर धर्म कुशवाहा, योगेन्द्र यादव, तारकेश्वर यादव, दिनेश गुप्ता आदि मौजूद थे।

माधोपुर से दो दिवसीय कृषक प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन



में वृद्धि हो सकती है। **किसानों का उत्साह और कार्यक्रम की सफलता** जनजातीय किसानों ने इस कार्यक्रम में उत्साहपूर्वक भाग लिया और प्रशिक्षण में दी गई जानकारी को अपने खेतों में अपनाने का आश्वासन दिया। किसानों ने फूलगोभी की पौध सामग्री प्राप्त करने के लिए केवीके के प्रति आभार व्यक्त किया और कहा कि यह उनके लिए अत्यंत

लाभकारी सिद्ध होगा। कार्यक्रम के समापन पर पौधा रोग विशेषज्ञ ने सभी उपस्थित किसानों को धन्यवाद दिया और कहा कि केवीके मधोपुर हमेशा किसानों के हित में कार्य करता रहेगा। यह आयोजन न केवल भगवान बिरसा मुंडा के प्रति श्रद्धांजलि थी, बल्कि किसानों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने का एक महत्वपूर्ण प्रयास भी था।

माधोपुर से दो दिवसीय कृषक प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन



(**वर्ल्ड न्यूज फीचर नेटवर्क**) **बेतिया।** भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का पूर्वी अनुसंधान परिसर, पटना एवं कृषि विज्ञान केंद्र, माधोपुर के संयुक्त तत्वाधान में मंगलवार को बेतिया के माधोपुर में फसल विविधीकरण द्वारा उत्पादन लाभप्रदता एवं जीविकोपार्जन में वृद्धि विषय पर दो दिवसीय कृषक प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में जिले के बैकुंठवा, रूल्ही, सेनुवरिया एवं दुबौलिया के लगभग 30 से अधिक किसानों ने भाग लिया। इस परियोजना के प्रधान अन्वेषक एवं फसल अनुसंधान प्रभाग के अध्यक्ष डॉ. संजीव कुमार ने किसानों को संबोधित करते हुए फसल विविधीकरण के महत्व एवं विभिन्न तकनीकों पहलुओं पर प्रकाश डालते हुए इसे अपने पारंपरिक कृषि प्रणाली में शामिल करने के फायदे पर प्रकाश डाला

साथ ही, उन्होंने आंकड़ों द्वारा समेकित कृषि प्रणाली द्वारा उत्पादकता एवं आय में वृद्धि की दृश्यां` संस्थान के वैज्ञानिक डॉ. अभिषेक कुमार ने फसल विविधीकरण द्वारा जलवायु परिवर्तन के प्रभाव के शमन हेतु कृषिवानिकी की उपयोगिता पर प्रकाश डाला ` भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का पूर्वी अनुसंधान परिसर, पटना द्वारा यह प्रशिक्षण कार्यक्रम 27 नवंबर 2024 तक चलेगा। इस प्रशिक्षण में कृषि विज्ञान केंद्र, माधोपुर एवं राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय, पूसा के क्षेत्रीय स्टेशन माधोपुर के विशेषज्ञों द्वारा भी विभिन्न विषयों पर व्याख्यान दिया जाएगा` इस कार्यक्रम को आयोजित करने में कृषि विज्ञान केंद्र, माधोपुर के वैज्ञानिक डॉ. अभिषेक प्रताप सिंह एवं डॉ. सौरभ दुबे का महत्वपूर्ण योगदान रहा।

चिकित्सा टीम ने बालिकाओं को दी महत्वपूर्ण जानकारी

■ महोबा

पूर्व माध्यमिक विद्यालय अकौना और महुआबांध में मुख्य चिकित्साधिकारी के निर्देश पर प्रभारी सीएचसी जैतपुर की देखरेख में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें आरबीएस की टीमों द्वारा माहवारी के समय बरती जाने वाली सावधानियों और स्वच्छता के बारे में जानकारी देकर छात्राओं को जागरूक किया गया। कार्यक्रम के तहत 196 बालिकाओं को निःशुल्क सैनेटरी पैड वितरित किए गए। पूर्व माध्यमिक विद्यालयों में आयोजित जागरूकता कार्यक्रम के तहत एफएचडब्ल्यू संगीता ने बताया कि मासिक धर्म अभी प्रतिबंधों से घिरी हुई है, लेकिन मासिक धर्म शर्म की बात नहीं बल्कि स्त्रियों के लिए गर्व का विषय है। कहा कि मासिक धर्म के बारे में गलत धारणाओं के कारण लड़कियों से भेदभाव किया जाता है, जिस कारण लड़कियों की मानसिकता पर भी दुष्प्रभाव पड़ता है और लड़कियां हीन भावना से ग्रस्त हो जाती हैं। उन्होंने बताया कि मासिक धर्म के दौरान आपको

अपनी सभी नियमित गतिविधियां करने में सक्षम होना चाहिए। मासिक धर्म के बाद एंठन कुछ स्वास्थ्य स्थितियों के कारण हो सकती है, कई स्त्रियों को मासिक धर्म चक्र से पहले या उसके दौरान पेट में ऐंठन का अनुभव होता है। फिर भी, मासिक धर्म के बाद भी एंठन होना संभव है। कार्यक्रम में मासिक धर्म दौरान स्वच्छता व सैनेटरी पैड के महत्व को समझाते हुए छात्राओं की झिझक को दूर करने का भी प्रयास करते हुए जागरूक किया गया। डा0 पीएन शर्मा ने बदलते मौसम में स्वस्थ रहने के टिप्स बताते हुए कहा कि इस दौरान व्यक्तिगत स्वच्छता सबसे महत्वपूर्ण है। कार्यक्रम दौरान पूर्व माध्यमिक विद्यालय महुआबांध में 78 और पूर्व माध्यमिक विद्यालय अकौना में 118 छात्राओं को सैनेटरी पैड का वितरण किया गया। कार्यक्रम दौरान ग्राम प्रधान अकौना उमा देवी, प्रतिनिधि गोपाल कुशवाहा विद्यालय के प्रधानाचार्य मोहम्माद इमरोज, सपना, दिनेश त्रिपाठी, नेतराम यादव, रवेंद्र पाल, हरेन खान, यशपाल सहित दोनों विद्यालयों में छात्राएं मौजूद रहीं।

कौन बनेगा मुख्यमंत्री ?

महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव ने भाजपा ने अब तक की सबसे बड़ी जीत तो हासिल कर ली है, लेकिन सवाल है कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा? देवेंद्र फडुनवीस या एकनाथ शिंदे? दावा तो देवेंद्र फडुनवीस का बनता है, क्योंकि भाजपा ने कुल 288 सीटों में से अकेले 132 सीटें जीतीं। शिवसेना (एकनाथ शिंदे) गुट ने 57 सीटें तो 41 सीटें एनसीपी (अजित पवार गुट) ने जीती हैं। सवाल ये है कि फडुनवीस को मुख्यमंत्री बनाया जाना एकनाथ शिंदे को मंजूर होगा? देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बनते हैं, तो फिर शिंदे क्या करेंगे? क्या उन्हें केंद्र में जिम्मेदारी दी जाएगी? शिंदे उपमुख्यमंत्री पद पर राजी हो जाएंगे, ऐसा लगता नहीं है। हां, अजित पवार हमेशा की तरह उपमुख्यमंत्री बने रह सकते हैं। अगर दो दिन बाद भी मुख्यमंत्री का फैसला नहीं हो पाया है, तो इसका मतलब यह है कि पेंच कहीं फंसा हुआ है। एक पेंच यह भी है कि 26 नवंबर यानी आज महाराष्ट्र विधानसभा का कार्यकाल खत्म हो रहा है। इससे पहले सरकार बनानी जरूरी है। ऐसा न होने पर राष्ट्रपति शासन लगाना पड़ेगा। हो सकता है रात किसी वक्त मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान हो जाए, क्योंकि भाजपा नहीं चाहेगी कि जनता में कोई गलत संदेश जाए। शिवसेना (एकनाथ शिंदे गुट) के सांसद नरेश म्हक्से ने

कहा है कि एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बने रहना चाहिए, क्योंकि लाडली बहिण योजना का आइडिया उनका ही था। इसका महायुति को बहुत फायदा हुआ है। शिंदे गुट के नेता बिहार पैटर्न पर मुख्यमंत्री बनाए जाने की बात कर रहे हैं। बिहार में जेडीयू की भाजपा से कम सीटें, लेकिन नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं। क्या देवेंद्र फडुनवीस को बिहार पैटर्न मंजूर होगा। यह भी तय है कि मुख्यमंत्री का फैसला दिल्ली से होगा। भाजपा हाईकमान जिस नाम का ऐलान करेगा, उसे मानना सभी की मजबूरी होगा। भाजपा हाईकमान का फैसला अंतिम होता है, वहां किंतु-परंतु की कोई गुंजाइश नहीं होती है। हालांकि नंबर के हिसाब से देवेंद्र फडणवीस आश्वस्त हो सकते हैं कि वही मुख्यमंत्री बनेंगे। एक तर्क दिया जा रहा है कि अगर देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री रह कर उपमुख्यमंत्री बन सकते हैं, जो शिंदे को क्यों आपत्ति होनी चाहिए? फिलहाल गेंद भाजपा हाईकमान के पाले में है। देखना यह है कि वह क्या फैसला लेता है। इतना जरूर कहा जा सकता है कि अजित पवार को उपमुख्यमंत्री पद से गुजारा करना होगा। उनके भाग्य में मुख्यमंत्री पद नहीं दिखता।

पाठकवाणी

महाराष्ट्र में बड़ी जीत

महाराष्ट्र में इतनी बड़ी जीत की उम्मीद शायद भाजपा समेत महायुति के समर्थकों को भी नहीं होगी। महाराष्ट्र में 10 से अधिक पार्टीज ने मिलकर दो गठबंधन बनाए थे। जिसमें महायुति आशा से अधिक सीटें प्राप्त करके महाराष्ट्र ही नहीं, पूरे देश को हैरान किया है। महाराष्ट्र चुनाव के प्रभाव दुरगामी में सिद्ध होंगे। इन चुनाव परिणाम से यह भी सिद्ध हुआ कि यदि एक दल वोट जेहाद के लिए किसी जाति विशेष को एकजुट करता है तो दूसरे दल के लिए धुवीकरण अपने आप हो जाता है। सोशल मीडिया के चरते जनता को ज्ञात होता रहा कि कौनसा दल सता की लालसा में कितना रसातल तक जा सकता है। फिर हारने के बाद विपक्षी दल द्वारा ईवीएम चुनाव आयोग से लेकर हर एजेंसी को कोसा गया वहां तक की महाराष्ट्र में ईवीएम खराब और झारखंड में ईवीएम अच्छी जैसी बचकाना बातें कही गईं। जो ईवीएम महाराष्ट्र में खराब है, वह झारखंड में कैसे सही हो गई? टेस्टा के मालि जबकि एलन मस्क कह रहे हैं कि 8 घंटे में 65 करोड़ वोटों की गणना कर लेना अद्भुत है और अमेरिका इस मामले में बहुत पिछड़ा हुआ है। कुल मिलाकर महाराष्ट्र की जीत ने कई नेताओं के मुगालें दूर किए हैं। तो एनडीए को नई एनजी दी है। इस जीत मैं आरएसएस की जबरदस्त भूमिका को भी श्रेय देना ही होगा। उसने अच्छा काम किया।

–सुभाष बुडानव वाला, रतलाम, एमपी

कुछ खास



बिना ट्रायल उमर खालिद को चार साल से जेल में रखा हुआ है। अब आज अगर आप आंदोलन करते हैं, तो आपको जेल में डाल दिया जाता है!

आज जेल जाने का मतलब है, आपके करियर, आपके उर्देश्य, आपके लक्ष्य, आपके जज्बात को तोड़ना और आपको पूरी तरह खत्म करना।

–हेमंत सोरेन, झारखंड के मुख्यमंत्री

आज का ट्वीट



“ गौतम अडानी का नाम लेते ही संसद की कार्यवाही रिकॉर्ड में जाना बंद हो गई। संसद स्थगित कर दी गई। मोदी अडानी एक हैं, तो अडानी जी

सेफ हैं। ”

–कृष्ण कांत

विचार

हमने इस तरह पाया संविधान

संविधान दिवस



शाहीन सबा

संविधान निर्माण के बाद कैलीग्राफर प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने अपने हाथ से लिखकर उसकी मूल (अंग्रेजी) प्रति तैयार की। इस काम में उन्होंने 6 महीने लगाए, 432 निबें घिसाईं और सैकड़ों बोटलें स्याही खपा डालीं। संविधान का मसौदा बनाने में दो साल, ग्यारह महीने और सत्रह दिन लगे। संविधान सभा के 165 दिनों के ग्यारह सत्र आयोजित किए गए थे।

‘हम भारत के लोग’ बेहद दर्पपूर्वक कहते हैं कि हमारा संविधान आकार में दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। मूल रूप से अंग्रेजी में लिखे गए इस संविधान में 117369 शब्द, 25 भाग, 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं, जबकि अब तक 106 संशोधन किए जा चुके हैं। लेकिन हममें से कम ही लोग जानते हैं कि इसके निर्माण की राह कितनी उजड़-खाबड़ राहों से गुजरी है और इसके निर्माताओं ने कितने कष्ट बुहारकर हमें इससे उपकृत किया है। इसे जानने चलें तो हम पाते हैं कि 1946 में आजादी की आहट सूंघ रहे अविभाजित देश में छः दिसम्बर को गठित संविधान सभा ने अपना काम शुरू ही किया था कि बंटवारे का कहर टूट पड़ा और वह भी विभाजित होने को अभिशप्त हो गई। 1946 में गठन के वक्त उसके कुल 389 सदस्यों में 15 महिलाएं थीं यानी उनका प्रतिनिधित्व चार प्रतिशत से भी कम था। विभाजन के बाद कुल सदस्यों की संख्या घटकर 299 हो गई जबकि महिलाओं की बारह। इनमें 229 सदस्य निर्वाचित होकर आये थे, जबकि 70 को मनोनीत किया गया था।

हां, इस सभा में देशी रियासतों तक के प्रतिनिधि शामिल थे, लेकिन स्वतंत्रता संघर्ष के महानायक महात्मा गांधी ने नैतिक कारणों से उसमें रहने से इन्कार कर दिया था। कहते हैं कि कांग्रेस के प्राबल्य के बावजूद सभा के सदस्यों में वैचारिक एकता या तालमेल के अभाव ने भी महात्मा को उससे दूर रहने के लिए प्रेरित किया था। अलबत्ता, उन्होंने संविधान निर्माण की शुभकामनाएं देने से गुरेज नहीं किया था।

एक और विडम्बना यह कि विभाजन के बाद बाबासाहेब डॉ. भीमराव अम्बेडकर भी भारतीय संविधान सभा में नहीं रह गये थे। कारण यह कि पूर्वी बंगाल का वह क्षेत्र, जिसके वोटों से वे अविभाजित भारत की संविधान सभा के लिए चुने गये थे, विभाजन के बाद पूर्वी पाकिस्तान में चला गया और वे भारतीय संविधान सभा के नहीं, पाकिस्तान की संविधान सभा के सदस्य हो गए। यह और बात है कि उन्होंने इस स्थिति को स्वीकार नहीं किया और बाद में कांग्रेस के एक सदस्य के इस्तीफे से रिक्त सीट का उपचुनाव जीतकर भारतीय संविधान सभा की सदस्यता पा ली। अनंतर, वे इस सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष बने और संविधान के निर्माता कहलाए। दिलचस्प यह कि अविभाजित भारत में संविधान सभा के गठन के तीन दिन बाद नौ दिसम्बर को जिस संविधान हाल में उसकी पहली बैठक हुई, उसे बाद में संसद भवन के सेंट्रल हॉल के नाम से जाना जाने लगा। तब उस बैठक के लिए उसकी भव्यतम सजावट की गई थी। विभाजन के बाद सभा की बैठकों में जहां प्रस्तावित गणराज्य के स्वरूप, नागरिकों के मौलिक अधिकारों, राजभाषा और राष्ट्रध्वज समेत अनेक विषयों पर गर्मार्ग विचारोत्तेजक बहसें हुईं।

बारह महिला सदस्यों ने संख्या में बेहद मामूली होने के बावजूद सभा की कार्रवाई में समय-समय पर कई महत्वपूर्ण हस्तक्षेप किये, लेकिन अपने समुदाय यानी महिलाओं के लिए किसी भी तरह के आरक्षण की मांग नहीं की। दक्षायनी वेलायुधन ने तो अनुसूचित जातियों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्रों के मुद्दे पर चली बहस में यह कहकर हंरान कर दिया कि वे किसी भी स्थान पर किसी भी तरह के आरक्षण के पक्ष में नहीं हैं। उनका कहना था कि दुर्भाग्यवश हमें आरक्षण की व्यवस्था स्वीकार करनी पड़ रही है, क्योंकि ब्रिटिश साम्राज्यवाद हमारे ऊपर कुछ ऐसे निशान छोड़ गया है कि हम हमेशा एक दूसरे से डरे रहते हैं। ऐसे में हम पृथक निर्वाचन क्षेत्रों को खत्म नहीं

कर सकते और हमें इसको सहना होगा क्योंकि यह एक अनिवार्य बुराई है। अनंतर, वे बाबासाहेब के साथ मिलकर कई बहसों में जाति से जुड़े कई मुद्दों को प्रकाश में ले आईं। उनके विपरीत संयुक्त प्रांत (अब उत्तर प्रदेश) से आई सभा की एकमात्र मुस्लिम महिला सदस्य बेगम एजाज रसूल (मुस्लिम लीग) ने देश की राष्ट्रभाषा, राष्ट्रमंडल का हिस्सा रहने या न रहने, आरक्षण, संपत्ति के अधिकार और अल्पसंख्यक अधिकारों पर बहसों में हस्तक्षेप किया।

प्रसंगवश, सभा में बिहार से चुनकर सभा में आई मशहूर कवयित्री सरोजिनी नायडू की कवि प्रतिभा का कोई सानी नहीं था। उनकी हाजिर-जवाबी का भी नहीं। बापू उन्हें ऐसे ही ‘भारतकोकिला’ थोड़े कहते थे। कहते हैं कि वे जब भी सभा को सम्बोधित करतीं, उसके सदस्यों को, कहना चाहिए, सम्पूर्ण सदन को मंत्रमुग्ध कर-के रख देती थीं। संभवतः इसी कारण डॉ. राजेन्द्र प्रसाद के सभा के स्थायी अध्यक्ष चुने जाते वक्त उसके अस्थायी (पीठासीन) अध्यक्ष डॉ. सच्चिदानन्द सिन्हा ने सरोजिनी को ‘बुलबुल-ए-हिन्द-द नाइटिंगेल आफ इंडिया’ कहकर बोलने के लिए आमंत्रित किया तो चुहल के इरादे से यह ‘अनुरोध’ भी कर डाला कि ‘वे हमें गद्य में नहीं, पद्य यानी कविता में संबोधित करें’। लेकिन सरोजिनी बोलने खड़ी हुईं तो

उनके नहले पर दहला जड़ दिया। पहले तो हंसाते हुए उनके अनुरोध को असंवैधानिक करार दे डाला, फिर उनका मान रखते हुए अपनी कोई कविता सुनाने के बजाय ‘एक कश्मीरी कवि’ (पंडित ब्रजनारायण चक्रवर्त, जो कश्मीरी मूल के भले ही थे, उत्तर प्रदेश के फैजाबाद शहर में पैदा हुए थे।) की लोकप्रिय खाक-ए-हिंद शीर्षक रचना की ये पंक्तियां सुनाई: बुलबुल को गुल मुबारक, गुल को चमन मुबारक, रंगीं तबीअतों को रंगेसुखन मुबारक। फिर क्या था, उन्होंने महफिल इस कदर लूट ली कि किसी को कातई पता नहीं चला कि उक्त पंक्तियां सुनाते वक्त उनकी यादशत उन्हें

दगा दे गई है, जिसके चलते उन्होंने उनका क्रम उलट-पलट डाला है। मूल रचना में वे इस क्रम में हैं: शैदां-ए-बोस्तां को सर्व-ओ-समन मुबारक। रंगीं तबीअतों को रंग-ए-सुखन मुबारक। लेकिन संविधान सभा के सबसे अलबेले सदस्य सच पृछिए तो संयुक्त प्रांत (अब उत्तर प्रदेश) से चुनकर आए लोकमान्य बालगंगाधर तिलक के दीवाने शायर हसरत मोहानी थे। पहले तो उन्होंने संविधान सभा में अपनी तीन साल की सेवाओं के बदले कोई मेहनताना लेने से साफ इन्कार कर दिया, यह कहकर कि उन्होंने जो कुछ भी किया, उसे मुल्क की खिदमत मानते हैं इसलिए उसकी एवज में कोई अपेक्षा नहीं रखते और अपनी ‘गरीबी में खुश’ हैं। फिर नेहरू के बहुत आग्रह करने लिया भी तो सिर्फ एक रुपया। ऐसा करने वाले वे सभा के इकलौते सदस्य थे।

संविधान निर्माण के बाद अपने वक्त के मशहूर कैलीग्राफर प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने अपने हाथ से लिखकर उसकी मूल (अंग्रेजी) प्रति तैयार की। इस काम में उन्होंने 6 महीने लगाए, 432 निबें घिसाईं और सैकड़ों बोटल स्याही खपा डालीं। लेकिन मोहानी की तरह उन्होंने भी इसकी फीस नहीं ली। बस, इतना चाहा कि उनकी लिखी प्रति के हर पेज पर उनका और अंतिम पेज पर उनके गुरु व दादा मास्टर राम प्रसाद सक्सेना का नाम रहे। उनकी इस इच्छा का सम्मान किया गया। यहां यह जानना भी दिलचस्प है कि संविधान का मसौदा बनाने में कुल मिलाकर दो साल, ग्यारह महीने और सत्रह दिन लगे थे और इस दौरान संविधान सभा के कुल मिलाकर 165 दिनों के ग्यारह सत्र आयोजित किए गए थे।

तीखी नजर

नारों का खेल और राजनीति



दिनेश विजयवर्गीय

हलिय की तरह राजनीतिक उठा पटक में रस रसीला स्वाद लेने वाले युवा मित्र मुंशी आज एक साहित्यिक समारोह में मिल गए। सुबह का का नाश्ता चल रहा था। वह मेरा और अपना नाश्ता, सर्दी की रेशम धूप में ले आया। हम कुर्सी में बैठकर पोहा और जलेबी के स्वाद का आनंद लेने लगे। वह जलेबी मुंह में रखता हुआ बोला, अभी हाल ही में हुए चुनाव में पिछले वर्ष हुए चुनाव के मुद्दों को सहेलाते हुए कुछ चेतन मन में प्रवेश कर गए, इसका नेताओं को पता ही नहीं चला।

लोकतंत्र के चुनावी माहौल में मुफ्त की रेवडी जैसे अपना प्रभाव दिखाती है, वैसे ही प्रभावी एवं न्यायन लिए हुए नारे भी अपना सतरंगी रूप दिखाने लगते हैं। नारों के बलबूते सत्ता का सिंहासन डोलने ही नहीं लगता, बल्कि समय आने पर पलट भी जाता है। कभी गरीबी हटाओ का नारा जन मानस में अच्छे से छा गया। संविधान बचाओ ने भी अपने थोड़े हाथ पैर चलाए और सहज ही सफलता दिला गया। उसने भी बहुत कुछ रंग जमाया। नारों की इन्हीं मारक क्षमताओं के बीच एक नया नारा आया। बटेण्डे तो कटेण्डे। इस नारे ने जैसे लोगों के मन में घर बना लिया। यह नारा मिसाइल की तरह अपने लक्ष्य पाने में बहुत कुछ प्रभावी है। पर कई जगह इस नारे की कड़वाहट को दूर करने के लिए इस पर मीठी चाशनी चढ़ा कर इसे परिष्कृत रूप से प्रस्तुत किया। अब इसका नया रूप हो गया एक रहोगे तो सब सेफ रहोगे। कुछ भी सोचें पर इन नारों ने अपना उद्देश्य प्राप्त करने में बड़ा योगदान दिया। अब आगे ऐसे ही नारों की डिमांड रहने वाली है।

मैंने कहा, यदि नारों में ही राजनीति में खेला करने की क्षमता है तो फिर तुम भी जन मन को प्रभावित करने वाले कुछ नारे बना डालो। अखबार रोज पढ़ते हो, जनता क्या कुछ चाहती है, यह तो पता लग ही जाएगा। बस उसी के आधार पर अपनी राजनीतिक साहित्यिक रूचि अनुसार नारे बनाओ। नारे सही और सामायिक प्रभावी बनने लगे तो राजनेता आपके पास आकर और भी ऐसे तो नारों के लिए कहने लगेंगे। भविष्य में भी नारों की नाव से ही चुनावी वैतरणी पार होने की संभावना बनी रहेगी। सभी राजनीतिक दल तुम्हारे पास नारे लिखवान आएंगे। पैसा मिलेगा और नाम भी। मुंशी मेरी बात से चुनाव में नारों की सवारी के महत्व पर आश्वस्त होता हुआ गरमा गरम चाय लेने चला गया। वह जल्दी चाय लेकर लौट आया। हम ऐसे ही गपशप करते चाय पूरी कर, समारोह के हॉल की ओर बढ़ गए।



साइबरवर्ल्ड

नए कलेवर में पुरानी कहानी

महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव के नतीजे शनिवार को आ गए। हरियाणा और जम्मु-कश्मीर की तरह इस बार भी मुकाबला एक-एक की बराबरी पर छूटा, यानी झारखंड में झामुमो और कांग्रेस गठबंधन को जीत मिली और महाराष्ट्र में महायुति को, जिसमें भाजपा, शिवसेना शिंदे गुट और अजित पवार की एनसीपी शामिल है। भाजपा समर्थक इस जीत से बेहद गदगद हैं और फिर से पूरे देश में यह विचार फैलाया जा रहा है कि मोदी ते तो मुमकिन है। हालांकि महाराष्ट्र की इस जीत को मुमकिन करने में सर्वोच्च न्यायालय से लेकर निर्वाचन आयोग जैसी संस्थाओं ने कितना योगदान दिया है, इसका विश्लेषण भी किया जाना चाहिए। जब भाजपा ने महाराष्ट्र में ऑपरेशन लोटस चलाकर शिवसेना और उसके बाद एनसीपी को तोड़ा, विधायकों को न जाने कौन से चमत्कारी तरीके से अपने साथ किया और फिर सरकार बनाई, तब उस सरकार को, राज्यपाल के फैसले को शीर्ष अदालत ने गलत बताया, लेकिन कमाल देखिए कि एक अवैध सरकार को कार्यकाल पूरा किए जाने का मौका दिया। निर्वाचन आयोग ने झारखंड के चुनाव तो समय से पहले कराए, लेकिन महाराष्ट्र के चुनाव हरियाणा के साथ न करवा कर जानबूझ कर उसे टाला, ल्योहार आने का वास्ता दिया गया। इन सारे अजीब लगने वाले फैसलों के पीछे क्या भाजपा के लिए पक्षपात किए जाने की बू नहीं आती ! महाराष्ट्र में उसे बड़ी जीत हासिल हुई है और झारखंड में अपनी ईमानदारी दिखाने के लिए जनादेश से निखलवाइ नहीं किया गया और फिर से झामुमो-कांग्रेस की सरकार बनने का रास्ता तैयार हो गया। झारखंड में निर्वाचन आयोग की विषमश्रुता और पारदर्शिता का मुगालता बने रहने दिया। लेकिन महाराष्ट्र में ये जोगिखम भाजपा नहीं उठा सकती थी, क्योंकि यहां की धरावी परियोजना में अडानी समूह के अरबों रुपए लगे हैं। हालांकि धरावी क्षेत्र में कांग्रेस को जीत मिली है। महाराष्ट्र में शरद पवार और उद्धव ठाकरे को भी भाजपा खत्म करना चाहती है, ताकि उसके सामने चुनौती देने वाले नेता न रहें। ये सारे काम तभी संभव थे, जब महाराष्ट्र में भाजपा जीतती।

–पलाश सुरजन की फेसबुक वॉल से

नजरिया



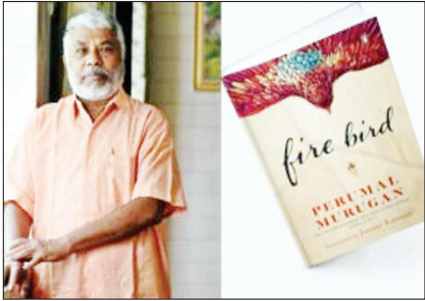
तनवीर जाफरी

साहित्य, मानवीय अभिव्यक्ति का एक ऐसा रूप है जो ‘संस्कृति’ का प्रसार करता है। साहित्य को समाज का दर्पण भी कहा जाता है। साहित्यकार अपनी रचनाओं में समाज के विभिन्न पहलुओं को दर्शाते हैं। साहित्य, जीवन प्रचलन के अनुसार गतिशील रहता है। गैर-काल्पनिक गद्य, काल्पनिक गद्य, कविता, नाटक, और लोक कथाएं आदि साहित्य के प्रमुख रूप हैं। साहित्यिक भाषा, किसी भाषा का वह रूप है जिसका उपयोग औपचारिक, अकादमिक, या विशेष रूप से विनम्र लहजे में लिखते समय किया जाता है। साहित्य समाज के मर्म का भी दर्पण है। यह साहित्य ही है जिसके द्वारा शब्दों के माध्यम से बड़े ही प्रभावी तरीके से अपनी बात कही और दूसरों तक पहुंचाई जाती है। हमारे देश में हिंदी व उर्दू साहित्य का एक सबसे प्रभावी नाम था मुंशी प्रेमचंद। उनके उपन्यासों व कहानियों में प्रायः गरीबी,सामाजिक अन्याय, सामाजिक व साम्प्रदायिक सद्भाव सहित तमाम मानवीय पहलुओं का जिक्र हुआ करता था। इसी तरह प्रेमचंद के समकक्ष अंग्रेजी साहित्य में भी ऐसे अनेक साहित्यकार हुए हैं, जिन्होंने सामाजिक मुद्दों और यथार्थवाद को इसी तरह संबोधित किया। इनमें चार्ल्स डिकेंस को जहां गरीबों के संघर्षों के चित्रण और सामाजिक अन्याय की आलोचना के लिए जाना जाता है वहीं विशेष रूप से ओलिवर ट्विस्ट और डेविड कॉपर फील्ड जैसी रचनाओं के लिये भी वे प्रसिद्ध हैं। इसी तरह मार्क ट्वेन के आख्यानों में अक्सर जाति और वर्ग के

भारतीय लेखकों सहित विश्व के सौ से अधिक उपन्यासकारों, लेखकों, कवियों, अनुवादकों और प्रकाशकों ने साहित्यिक पुरस्कार की आयोजक कंपनी जेसीबी को खुला पत्र लिखकर यह कहा है कि ‘जेसीबी साहित्य पुरस्कार’ कोई पुरस्कार नहीं, बल्कि पाखंड है

विषयों पर प्रकाश डाला जाता था, जैसा कि द एडवेंचर्स ऑफ हकलबेरी फिन में देखा गया है। वहीं टोनी मॉरिसन जोकि बेलव्ड जैसे उपन्यासों में अफ़्रीकी अमेरिकी अनुभवों और सामाजिक मुद्दों की उनकी खोज प्रेमचंद के हाशिए पर पड़े समुदायों पर ध्यान केंद्रित करने के साथ प्रतिध्वनित होती है। प्रेमचंद को ही तरह इन लेखकों ने भी अपने आख्यानों का उपयोग सामाजिक मानदंडों और अन्याय की आलोचना करने के लिए किया।

हमारा देश गांधी के सत्य अहिंसा के सिद्धांतों पर चलने वाले देश के रूप में विश्व प्रसिद्ध है। इसलिये यहाँ हिंसा,विध्वंस,नफरत,विद्वेष,साम्प्रदायिकता तबाही बर्बादी जैसे अमानवीय पहलुओं को कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। परन्तु ब्रिटिश कंपनी ने सी बैमफोर्ड एक्सकेवेटर लिमिटेड (जेसीबी) की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी जेसीबी (इंडिया) जो ब्रिटिश कंजर्वेटिव पार्टी के सबसे प्रभावशाली दान दाताओं में से एक रही है, इसी जेसीबी कंपनी ने लेखकों के लिए एक साहित्य पुरस्कार की स्थापना की है। गौर तलब है कि यही जे सी बी कंपनी है जो इस्त्राइली रक्षा मंत्रालय के साथ एक अनुबंध के तहत फिलिस्तीन में मकानों को ध्वस्त करने



और अवैध इस्त्राइली बस्तियों के विस्तार के लिए जेसीबी बुलडोजर मुहैय्या करा रही है। इसी जेसीबी के बुलडोजर गजा में तबाही मचाए हुए हैं। भारत में भी सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद भले ही जेसीबी के बुलडोजरों द्वारा दह्राए जाने वाले भवनों की संख्या में अब विराम लग गया हो। परंतु गत एक दशक से देश के खासकर भारतीय जनता पार्टी शसित अनेक राज्यों में सत्ता शक्ति का दुरुपयोग करते हुए धर्म व जाति-विशेष के लोगों को निशाना बनाया गया और शासन द्वारा अदालत की शक्तियों को अपनी हाथों में लेने की कोशिश की गई, जिसने पूरे विश्व में मानवीय संवेदनाओं को झकझोर कर रख दिया। इससे भी शर्मनाक बात यह है कि इसी विध्वंसकारी मशीन का भारत से लेकर अमेरिका तक इन्हीं दक्षिणपंथियों द्वारा महिमामंडन किया गया। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर इस मशीन का विदेशों में प्रदर्शन किया गया। और हद तो तब हो गई, जब गांधी के राज्य गुजरात में अप्रैल 2022 में तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ब्रिटिश जेसीबी कंपनी का दौरा करते हैं और साथ ही बुलडोजर पर खड़े होकर फोटो कराते हैं। साथ ही अपने इसी दौर में वे गांधी जी के आश्रम में जाकर उनका चरखा भी चलाते

हैं? एक नोट दस रुपये का था, दूसरा सौ रुपये का और तीसरा हजार का। इसके बाद स्वामीजी ने पूछा कि इनमें क्या अंतर है? लोग चुप रहे और स्वामी जी की ओर देखते रहे। स्वामीजी ने समझाया, ये तीनों नोट एक जैसे कागज पर छपे हैं। कागज के पहले टुकड़े से दस रुपये की चीज खरीदी जा सकती है तो दूसरे से सौ रुपये की और तीसरे से हजार की। ये कागज पर लगी मोहर या छाप द्वारा निर्धारित हुआ है। हमारा जीवन भी एक कोरे कागज की तरह ही है। हम चाहें तो उस पर दस रुपये के बराबर छोटी-मोटी विशेषता या गुण की मोहर लगा सकते हैं और चाहें तो हजार रुपये या उससे भी अधिक की कीमत के गुणों की मोहर लगा सकते हैं। जैसी छाप या सोच वैसा जीवन। इस संसार रूपी छापे खाने में मन रूपी कागज पर केवल सात्विक व जीवनेपयोगी उच्च विचारों की मोहर लगाकर ही जीवन को हर प्रकार की उच्छृंखला प्रदान की जा सकती है।



हैं। सवाल यह है कि जो जेसीबी कंपनी भारतीय लेखकों की विविधता का जश्न मनाते हुए साहित्यिक पुरस्कार देने के घोषणा कर रही हो, उसी कंपनी द्वारा ऐसी विध्वंसकारी मशीन का निर्माण व जनसंहारक उपयोग किया जाना, जिससे कि वह दंड के रूप में लाखों लोगों के जीवन, उनके घरों व आजीविका को नष्ट करने में भागीदार हो, ऐसे दोहरेपन में आखिर 'साहित्यिक पुरस्कार' की क्या गुंजाइश?

यही वजह है कि भारतीय लेखकों सहित विश्व के सौ से अधिक उपन्यासकारों, लेखकों, कवियों, अनुवादकों और प्रकाशकों ने ब्रिटिश बुलडोजर निर्माता और एक साहित्यिक पुरस्कार की आयोजक कंपनी जेसीबी की आलोचना करते हुए एक खुला पत्र लिखकर साफ शब्दों में यह कहा है कि ‘जेसीबी साहित्य पुरस्कार’ कोई पुरस्कार नहीं बल्कि यह इस कंपनी का एक पाखंड है क्योंकि ‘जेसीबी साहित्य पुरस्कार’ की घोषणा करने वाली यही कंपनी भारत और फिलस्तीन में गरीबों तथा हाशिये पर पड़े गरीब लोगों की जिंदगी ‘उजाड़’ रही है और जो दंड के रूप में इतने सारे लोगों के जीवन और आजीविका को नष्ट करने में भागीदार है। ‘लेखकों ने पत्र में यह भी लिखा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने विभिन्न राज्यों में मुसलमानों के घरों, दुकानों और उपासना स्थलों को ध्वस्त करने के लिए ‘व्यवस्थित अभियान’ में लगातार जेसीबी बुलडोजर का इस्तेमाल किया है और इस परियोजना को ‘बुलडोजर न्याय’ का नाम दिया गया है, जो बेहद परेशान करने वाला है। मानवीय संवेदनाओं का सम्मान करने वाले लेखकों के लिये यह महत्वपूर्ण व जरूरी है कि वे मानवाधिकारों के इस घोर उल्लंघन के खिलाफ आवाज उठाएं, क्योंकि ‘विध्वंस’ को महिमामंडित करना शर्मनाक है।

